Indian Streams Research Journal
Vol - I , ISSUE - IV May 2011 **ISSN:-2230-7850**

गठबंधन सरकार : एक अध्ययन

डॉ. बबली नागर

उज्जैन

सारांश

प्रस्तुत शोध अध्ययन में गठबंधन सरकार की अवधारणा और गठबंधन सरकारों की विभिन्न थ्योरी पर प्रकाश डाला गया है।

प्रस्तावना :

भारतीय राजनीति में गठबंधन का अर्थ हो गया है कि कैसे भी किसी भी कीमत पर और किसी भी प्रकार सहयोगी दलों को प्रसन्न रखो, चाहे इस प्रयास में अपनी पार्टी के सदस्यों के हितों की अवहेलना हो। पार्टी की नीतियों की अवहेलना, और राजनीति किसी भी स्तर तक गिर जाये पर गठबंधन चलना रहना चाहिये।

गठबंधन की राजनीति में विभिन्न दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो होना यह चाहिये कि राजनीति में एक दल की तानाशाही से मुक्ति मिले और गलत नीतियों पर एक रूकावट उत्पन्न हो, पर ऐसा कुछ कम से कम भारत की गठबंधन की राजनीति में तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता।

गठबंधन में शामिल नहीं होने से पार्टी की विचारधारा की उतनी भूमिका नहीं होती जितनी की सामाजिक आधार की जनता दल इसका बढ़िया उदाहरण हैं कांग्रेस विरोध सत्ता के गलियारों में कही खो गया। १९७७, १९८९, १९९६, १९९७ के गठबंधन में इसकी अहम भूमिका रही। इस गठबंधन के निर्माण में कांग्रेस विरोध सबसे प्रमुख तत्व रहा था। १९७७, १९८९ में यह दिखा भी और अपने चरम पर रहा किन्तु १९९६, १९९७ में जब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में अपने पैर पसार चुकी थी। अब भारतीय जनता पार्टी के भय के कारण से विरोधी दल एकजुट हुए।

१९८९, १९९६, १९९८ के गठबंधन को फनपबा Fix (क्विक फिक्स) गठबंधन भी कहा जा सकता है। अवसरवादी राजनीति की यह चरम सीमा थी।

गठबंधन के निर्माण में पिछले अनुभवों की उतनी भूमिका नहीं होती है, जितनी की समयानुसार परिस्थिति की। गठबंधन में हमारी क्या जरूरत है, हम कितना मोल-भाव करने की स्थिति में है, और हमारा क्या फायदा होगा यही, यही तत्व काम करते हैं। यही कारण है कि भारतीय राजनीति में ढेरों उदाहरण पड़े है जबकि दो दलों की आपसी खींचतान के कारण गठबंधन टूटा और अगली बार फिर सत्ता प्राप्ति की बात आई और गठबंधन बनने लगे।

जब दो पार्टियों की लगभग बराबर सीट मिलती है और ये दोनों पार्टियाँ अकेले अपने दम पर या अपने सहयोगियों के साथ भी सरकार बनाने में सफल नहीं होते, तब तोड़-फोड़ की राजनीति होती है, और कोई एक दल का विभाजन होता है।

१९९९ में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार गिरी क्योंकि उनका एक घटक ए.आई.ए.डी. एम.के. मंत्रीमंडल के गठन से संतुष्ट नहीं था और बाकी सब दल समर्थन में थे।

एक विशेष उदाहरण गठबंधन की राजनीति का उत्तर प्रदेश में १९९७ की राजनीति में रहा जबकि भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन में शामिल होने वाले प्रत्येक विधायक मंत्री पद से नवाजा। दो वर्ष बाद मुलायम सिंह ने इसी फार्मूले को दोहराया।

गठबंधन का एक अन्य प्रकार होता है जबकि कोई पार्टी गठबंधन में शामिल नहीं होती वरन् बाहर से समर्थन देती है और सत्ता के सारे सूत्र प्रत्यक्ष रूप से अपने पास रखती है। यहां पर कांग्रेस द्वारा १९९६-१९९८

में बाहर से समर्थन (देवगौड़ा+गुजरात/ल) वहीं १९९९ में भारतीय जनता पार्टी और कम्यूनिष्टों द्वारा वी.पी. सिंह को बाहर से समर्थन दिया।

इस तरह की व्यवस्था में गठबंधन दो प्रकार से लाचार होता है। पहला जब जी चाहे तब गठबंधन से समर्थन वापस ले लिया जावे। वहीं दूसरी और कई बार पार्टी विशेष में इस बात को लेकर मतभेद पैदा हो जाते है कि गठबंधन में शामिल हुआ जाए अथवा नहीं।

गठबंधन में शामिल होने के मुद्दे पर निर्णय करने का अधिकार अधिकांशतः पार्टी के अभिजन वर्ग को होता है और पार्टी का निम्न संगठन इसका अनेक अवसरों पर विरोध भी करता है। जैसे कांग्रेस द्वारा उत्तर प्रदेश में २००३-०४ में मुलायम सिंह को समर्थन का यू.पी. कांग्रेस ईकाई ने विरोध किया। पर केन्द्र ने गठबंधन किया और परिणाम उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव २००४ में कांग्रेस को अपेक्षित सीट नहीं मिल पाई।

१९९८ तथा १९९९ के लोकसभा चुनाव में गठबंधन सरकारें ही रहीं, १९९८ में तेलगुदेशम पार्टी, जनता दल और गठबंधन कांग्रेस के साथ भी वहीं। १९९९ में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जाने का निर्णय किया और फिर समाजवादी पार्टी गठबंधन से बाहर हुई।

अनेक अवसरों पर सालों साल के विरोध पार्टियाँ, वे दल जो कि तात्कालिक चुनाव में भी विरोध में लड़े थे। कई अवसरों पर वे गठबंधन में शामिल हो जाते है ऐसे गठबंधन शुद्ध रूप से अवसरवादी कहे जा सकते है।

गठबंधन बनने के बाद जितनी जद्दोजहत गठबंधन में मंत्रीपद वितरण को लेकर नहीं होती उससे कहीं अधिक जद्दोहजत पार्टी के भीतर ही होती है।

भारत के राज्यों में १९६७ के पश्चात् तथा केन्द्र में १९७७ के बाद गठबंधन सरकार की राजनीति दृष्टिगोचर हुई चाहे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे पर कहीं न कहीं राज्य की राजनीति में क्षेत्रीय दलों ने अपनी पैठ जमाई।

भारत के केन्द्र में १९७७, १९८९, १९९६, १९९९, २००० तक लगातार गठबंधन सरकारें बनी और अस्तित्व में रहीं।

अख्तर माजिद ने कहा है-

Politics in India is always bound to be coalition in general sense though it is contrained within different political parties.

इनके अनुसार भारतीय राजनीति गठबंधन की राजनीति हमेशा से रही फर्क इतना है कि पहले गठबंधन पार्टी विशेष में सीटों का बटवारा, मंत्रीमंडल में पदो ंके बटवारे को लेकर होता था। प्रत्येक पार्टी में जाति, धन/धर्म, क्षेत्र, वर्ग आदि के आधार पर ही सत्ता के लाभ के पदों का बंटवारा होता है।

गठबंधन की राजनीति में दो प्रकार के गठबंधन होते हैं।

१.चुनाव पूर्व का गठबंधन
२.चुनाव पश्चात् गठबंधन

१९८९ नेशलन फ्रंट, १९९६ यूनाईटेड फ्रंट, १९९९ का नेशनल डेमोक्रेटिक अलाईज चुनाव पश्चात् गठबंधन।

१९९८-१९९९ भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की सरकार चुनाव पूर्व और चुनाव पश्चात् दोनों ही गठबंधन का उदाहरण है।

सत्ता में शक्ति के आधार पर गठबंधन का वर्गीकरण

बड़ी पार्टी के द्वारा निर्णय लिया जाना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार इसका उदाहरण है। निर्णय लेने में वाजपेयी जी के नेतृत्व में ठीक-ठीक ही निर्णय करता था। फिर जार्ज फर्नाडिस के नेतृत्व वाली समन्वय समिति उस पर विचार करती थी और सभी गठबंधन के दल इसे मानते थे किन्तु हमेशा ही ऐसा नहीं होता था। अनेक अवसरों पर गठबंधन के छोटे सहयोगियों की बात को भी बराबर की तरदीब दी जाती थी।

नेशनल फ्रंट और यूनाईटेड फ्रंट अच्छे उदाहरण है। १९७७ के बाद पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु के नेतृत्व वाली सरकार भी दूसरा बढ़िया उदाहरण है।

भारत में वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली १९९९-२००४ की सरकार को छोड़कर केन्द्र में कोई और सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। दूसरे निम्न कारक है-

गठबंधन द्वाना निम्न बहुमत की स्थिति।
बाहर से दिया हुए समर्थन को वापस लेना।

विचारधाराओं के मुद्दे पर मतभेद।
नेतृत्व का विवाद।
पार्टियों के भीतर मतभेद।
चुनाव में स्वयं के अच्छे अवसर की संभावना।
गठबंधन के नेतृत्व की अन्य दलों के आगे की जा रही अवहेलना।
विपक्ष द्वारा गठबंधन को तोड़ने का प्रयास।

१९७९ की जनता सरकार गिरी – चरणसिंह जिम्मेदार।
१९९० नेशनल फ्रंट गिरी – भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार।
१९९६-९८ यूनाईटेड फ्रंट गिरी – कांग्रेस जिम्मेदार।
१९९९ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व – ए.आई.ए.डी.एम.के. जिम्मेदार।

की सरकार का पतन
गठबंधन की राजनीति के चार माडल होते है।

एकदल के मजबूत नेतृत्व और संख्या के साथ अन्य छोटे दलों का गठबंधन। यहां पर गठबंधन के बड़े दल की यह स्थिति होती है कि अगर छोटे दल समर्थन वापस भी ले ले तब भी छोटे दल सरकार न गिरा सके। जर्मन जनवादी गणराज्य की सरकारे, भारत में पश्चिम बंगाल में सी.पी.आई.(एम) के नेतृत्व वाली साम्यवादी सरकारें।

ऐसा गठबंधन जिसमें की सभी दलों की समान ताकत हो फ्रांस के चतुर्थ रिपब्लिक में ऐसी सरकारें है। भारत में केरल में ऐसी सरकार का प्रयोग हुआ जो काफी सफलतापूर्वक हुआ।

एक जैसे विचारों वाली पार्टियों का गठबंधन जो अपनी विरोधी विचारधारा वालों को सत्ता में न आने देना चाहते। फ्रांस के लिआन ब्लम की १९३. के दशक की सरकार फ्रांसिज्म और नाजिज्म के विस्तार को रोकने हेतु बनी थी। भारत में १९६७-१९६८ में नौ राज्यों में सरकारें इसी कारण से बनी कि कैसे भी कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना है।

राष्ट्रीय सरकार का गठन

ब्रिटेन में द्वितीय विश्व युद्ध के समय की सरकार जिसमें एटली प्रधानमंत्री तथा निस्टल चर्चिल उपप्रधानमंत्री बने। कारगिर संकट के समय वाजपेयी सरकार के समक्ष भी राष्ट्रीय सरकार का प्रपोजल आया था पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया।

भारत में गठबंधन सरकार का अस्तित्व भारत के संविधान से भी पुराना है। भारत में पहली गठबंधन सरकार का दौर भारतीय शासन अधि. १९३५ के तहत कुछ चुनावों के चुनाव पश्चात् अस्तित्व में आया जबकि कांग्रेस ने मद्रास, यूनाईटेड प्राविन्स, बिहार, सेन्ट्रल प्राविन्स तथा उड़ीसा में स्पष्ट बहुमत पाया। मुंबई में कांग्रेस को लगभग आधी सीटें प्राप्त हुई। इस प्रकार ११ में से ९ राज्यों को कांग्रेस ने अपने नेतृत्व में गठबंधन सरकारें बनाई।

१९४६ की सरकार भी एक गठबंधन सरकार ही थी। हिंदु, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई और एंगलो इंण्डियन को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया था। यह सरकार प्रथम आम चुनाव १९५२ तक अस्तित्व में बनी रही। स्वतंत्र भारत की पहली गठबंधन सरकार का श्रेय पेप्सू सरकार को जाता हैं

Pepsu Patiala and the East Punjab State Union.

१९५२ में जबकि विधानसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। गैर कांग्रेसी दल एकजुट हुए और इन्होंने गठबंधन सरकार गठित की।

१९५२ के चुनाव में निम्न राज्यों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ।
उड़ीसा – गणतंत्र परिषद
पंजाब – पेप्सू
त्रावणकोर (कोचीन) – कम्यूनिस्ट
मद्रास – कम्यूनिस्ट आंध्र क्षेत्र में
प्रोद्रविडियन ग्रुप – तमिलनाडू क्षेत्र में
कलकत्ता – कम्यूनिस्टो की मजबूत स्थिति

राजस्थान में बमुश्किल कांग्रेस ने बहुमत के अंक को छुआ।

अक्टूबर १९५३ में त्रावणकोर कोचीन अलग राज्य बना और १९५४ के चुनाव में पीएसपी ने सरकार बनाई। कांग्रेस के समर्थन से १९५६ की गर्मियों तक यह सरकार बनी और फिर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ।

१९५७ से १९६१ उड़ीसा में गठबंधन सरकार रही कांग्रेस तथा गणतंत्र परिषद की जिसमें की कांग्रेस की सीट अधिक होने से वह निर्णायक भूमिका में रही, वहीं १९६०-६४ तक केरल में गठबंधन सरकार रहीं पीएसपी मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस की।

१९६७-१९८१ चुनाव भारतीय राजनीति में एक दल के प्रभुत्व की समाप्ति का चुनाव भी कहा जा सकता है। अब एक दलीय सरकार से बहुदलीय सरकार की ओर भारतीय लोकतंत्र ने अपने कदम बढ़ाना प्रारंभ किये।

कांग्रेस का वोट ७.५ प्रतिशत गिरा और जहां पिछले लोकसभा में कांग्रेस ने ७४ प्रतिशत सीट पाई थी इस बार यह प्रतिशत गिरकर ५४ हो गया।

इस चुनाव के बाद नौ राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडू और केरल में गैर कांग्रेसी सरकारें अस्तित्व में आई।

१९६७ के पहले तक भारत के प्रत्येक राज्य में कांग्रेस की या कांग्रेस के सहयोग वाली सरकार रही थी। सिवाय जम्मू कश्मीर में नेशनल कांफ्रेस।

केरल में सीपीआई (१९५७-५९)
नागालेण्ड १९६३ नागा नेशनल कांफ्रेंस

१९६७ के चुनाव में डी.एम.के. को छोड़कर अन्य कहीं पर भी किसी भी एक दल ने कांग्रेस को नहीं हराया था और मद्रास को छोड़कर अन्य आठ राज्यों में विभिन्न दलों का गठबंधन की सरकारें बनी।

बिहार - SSP+PSP+ जनसंघ+जन क्रांतिदल+सीपीएस की संविद सरकार

पंजाब- अकाली दल (सप्र ग्रुप)+सीपीआई+सीपीआई(एम) अकाली दल (मास्टर ग्रुप)+ एसएसपी रिपब्लिक पार्टी की संविद सरकार।

प. बंगाल - यूनाईटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (सीपीआई(एम) + बंगला कांग्रेस + १४ अन्य छोटी पार्टिया।
उड़ीसा - स्वतंत्र पार्टी + जन कांग्रेस + किसान कांग्रेस की संविद सरकार
केरल - सीपीआई(एम) + सीपीआई + एसएसपी + आएसपी + केजेपी + केएसपी + मुस्लिम लीग।

हरियाणा में कांग्रेस की सरकार के १३ कांग्रेसी विधायकों ने सरकार के खिलाफ वोट दिया और सरकार गिराई। विपक्ष के साथ मिलकर इन्होंने यूनाईटेड फ्रंट बनाया। जनसंघ तथा स्वतंत्र पार्टी ने गठबंधन में होने के बाद भी सरकार में भागीदारी नहीं की। १९६७ में राव विरेन्द्र सिंह के नेतृत्व वाली यह सरकार पार्टी में टूट-फूट होने से अल्पमत में आ गई।

मध्य प्रदेश में १९६७ में कांग्रेस में टूट हुई और वे यूनाईटेड फ्रंट में जा मिले और फिर संविद सरकार बनी। यह संविद सरकार १९६९ तक चली।

उत्तर प्रदेश में सी.बी. गुप्ता की सरकार गिराने और कांग्रेस में टूट के बाद संविद सरकार बनी। यह १७ फरवरी १९६८ को भंग कर दी गई।

अधिकांश राज्य की संविद सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और समय के पहले ही भंग हुई। इससे कांग्रेस के विरूद्ध विभिन्न दलों की एकजुटता को काफी धक्का पहुँचा।

इन सरकारों की असफलता के प्रमुख कारणों में बहुत बड़े पैमाने पर दलों में टूट-फूट, नेतृत्व के मुद्दे पर होने वाले विवाद तथा न्यूनतम साझा कार्यक्रम को कड़ाई से लागू नहीं किया जाना रहा।

एक आश्चर्यजनक तथ्य रहा है कि जहां १९५७ से १९६७ के बीच में विभिन्न दलों के विधायकों द्वारा ५४२ दलबदल किये गये, वहीं १९६७-६९ के दो वर्ष के अंत में ४३८ दलबदल हुए।

रजनी कोठारी के शब्दों में-

"The Congress was a characteristic catch all party trying to encompars, all the more relevant segment of political reality, including a great many oppositional segment, it was like a hindu society in mininatire, accommodation and algglomeralive given lew to specificly and differentiation and more to conecenres and catholrism, the congress was grand coalition with a great historic ante cedents and Itself representating the Indian natia most of its ettemtial.

१९६७ के पहले तक कांग्रेस Umberla Organization थी जिसमें एक ही छाते के नीचे विभिन्न नेता इकट्ठे होते थे। क्षेत्रीय नेताओं का भी कांग्रेस बखूबी उपयोग किया करती थी।

माईना विनर के शब्दों में–

"The taste of building the congress coalition was cased by traditional values and rates of confiliation that congressman astutely taste up.

एंजला बर्नन के शब्दों में १९६७ के चुनाव–

"She described it as a pattern which moved from one party dominanes to moderately competitive multi party system.

रजनी कोठारी १९६७ के चुनाव परिणामों पर टिप्पणी करते हुए कहती है–

"The only non congress parties that proved coalitionable after 1967 was the Marks Communist in Kerala. The DMK in Madras and Swatantra Jan Congress in Orissa.

गठबंधन की राजनीति– यूनाईटेड फ्रंट का प्रयोग

प्रो. नारायण के अनुसार– "Coalition govt. is a typical situation of make coalition with another to fill jointly the same time to forge a visable political identity.

भारत में गठबंधन राजनीति की शुरूआत के कही पहले आजादी के वर्ष के दौरान उन्नीसवी शताब्दी के अंतिम हिस्से और २०वीं शताब्दी की शुरूआत में एक और कांग्रेस के बैनर तले विभिन्न दलों की एकजुटता रही। क्रांतिकारी संगठनों की बंगाल और महाराष्ट्र की राजनीति ने एकजुटता इसके अच्छे उदाहरण है। १९८७ की कांग्रेस की दूर तक और १९१६ के लखनउ समझौते के बाद नरम और गरम दल एकजुट होकर कांग्रेस के बैनर तले संघर्ष दल रहे। कांग्रेस में जवाहर लाल नेहरू, सुभाष चन्द्र बोस जैसे समाजवादी भमवेन्द्र नाथ जैसे सामाजिक, क्रांतिकारी और मानवतावादी आदि अनेक स्वतंत्रता सेनानी एकजुट होकर रहे।

१९२३ में कांग्रेस में विधानसभाओं में शामिल होने नही होने के प्रश्न पर एकबार फिर कांग्रेस में टूट–फूट और अगवा रहे और भारत के प्रथम और सबसे समृद्ध कहे जाने वाले राजनीतिक घराने के श्री मोतीलाल नेहरू और उनके सहयोगी चिरन्जनदास/चित्तरंजनदास इन्होंने एक अलग दल स्वराज पार्टी बनाई चुनाव में भाग लिया और विधानसभा में दाखिल हुए। इस प्रकार भारतीय राजनीति में दल से अलग होकर नवीन दल का निर्माण और फिर मूल दल में वापसी यह सब समय के साथ होता ही रहा है।

गठबंधन की बात उस स्थिति में आती है जब तीन या तीन से अधिक नेता अपने एक दूसरे से भिन्न अभिलाषा और लालसाओं को लेकर सत्ता प्राप्ति का प्रयास करते है।

डुवर्जर ने गठबंधन को तीन प्रकार से बांटा हैं–

१.इलेक्टोरल
२.पार्लियामेन्टली
३.गर्वमेंटल

गठबंधन पर आधारित विभिन्न थ्योरीज

१.एन. परसन थ्योरी

इस विचारधारा को रिकर द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसे आगे जाकर जान वान न्यूमैन तथा मोरगेन्स्ट्रान ने आगे बढ़ाया। यह विचार न्यूनतम सदस्यों की सत्ता के विचार को लेकर चलती है। अर्थात् गठबंधन में जितने कम दल शामिल होगे, गठबंधन उतना ही सफल रहेगा। बंगाल में चार दलों का गठबंधन (सीपीआई + सीपीएम + आरएसपी + फारवर्ड ब्लाक) इसका अच्छा उदाहरण है। इस थ्योरी के मूल में यह बात शामिल है कि जितने अधिक दल गठबंधन में शामिल होगे उतनी अधिक विविधता विचारों में आएगी और यह राजनैतिक स्थिरता के लिए खतरा होगा। किन्तु १९९८ के लोकसभा से वाजपेयी जी द्वारा २४ दलों के एनडीए को कुशलतापूर्वक चलाना और अपना कार्यकाल पूर्ण करना इस विचारधारा से मेल नहीं खाता।

२.एवरी गेम थ्योरी

इस विचारधारा की मान्यता है कि गठबंधन तब अस्तित्व में आयेगा जबकि कोई बड़ा दल जो राजनीति में परिवर्तन करने की स्थिति में है। यथास्थिति में कुछ परिवर्तन चाहता है और वह इस स्थिति में है कि वह परिवर्तन कर सके तब ऐसी स्थिति में एक नवीन व्यवस्था उभरकर सामने आती है जिसे की बाकी दलों को मजबूरन मान्य करना होता है।

१९९७-१९९८ के दौरान एच.एन. देवेगोड़ा के नेतृत्व में गठबंधन सरकार जनता पार्टी की थी और तब कांग्रेस ने अपना बाहरी समर्थन इस बात के साथ वापस लिया की अगर जनता पार्टी गठबंधन अपना नेता बदले तब ही कांग्रेस अपना समर्थन जारी रख सकती है। कांग्रेस यहां पर यथास्थिति में परिवर्तन अपनी मर्जी के हिसाब से करना चाहती थी और फिर इन्द्रकुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया गया।

३.जीरो सम कन्डीशन

इस विचारधारा के अनुसार वह स्थिति जिसमें की विजेता वह कुछ जीत लेता है जो कि हारा हुआ हारता है (ट्रिकर) इससे हम आसान तरीके में प्रकार समझ सकते है कि राजनीति में अनेक बार ऐसी स्थिति आती है जबकि एक दल टूट जाता है। अगर टूटे हुए दल के सदस्य जाकर दूसरे दल में मिलते है और उस दल की शक्ति बढ़ाकर उसे सत्ता में भागीदारी प्रदान करते है तो यही जीरो थ्योरी सम कन्डीशन है।

साथ ही कुछ अवसरों पर यह भी होता है कि एक पार्टी का एक धड़ा अलग होकर पृथक चुनाव लड़ता है और अपनी मूल पार्टी की सीटों को हथिया लेता है। इस प्रकार मूल पार्टी को जितनी सीटों का नुकसान होता है नये बने दल को उतना ही फायदा होता है। १९८९ के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से निकलकर व्ही.पी. सिंह द्वारा बनाई गई जनता दल इसका अच्छा उदाहरण है।

४.टी. केप्लाज थ्योरी

Parties will prefer the coalition that would enable them to control two other then control one another.

अर्थात् गठबंधन में प्रमुख राजनीतिक दल यह चाहता है कि अन्य सभी पार्टियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता है न कि गठबंधन में शामिल पार्टियाँ एक दूसरे से लड़ती रहे। इसमें प्रमुखतः एक पार्टी प्रभुत्व की ओर इंगित किया है, जिसमें की अन्य पार्टियाँ अपनी शक्ति और क्षमता में बड़ी पार्टियों से बहुत छोटी होती है। १९९८ में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में २४ दलों के गठबंधन की सरकार का गठन हुआ जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ सबसे बड़ा दल था वरन् अन्य दलों से इतना अधिक शक्तिशाली भी था कि वह अन्य छोटे दलों पर आसानी से नियंत्रण कर सके। यही स्थिति १९९१ के चुनाव के बाद श्री नरसिंहरावजी के नेतृत्व में गठित कांग्रेस प्रभुत्व वाली गठबंधन सरकार में भी देखी गई।

५.गेमसन्स मिनिमम रिसोर्स थ्योरी

गठबंधन की राजनीति की यह थ्योरी यह सूचित करती है कि वह पार्टी जो कि गठबंधन में बंधती है अपना अधिकतम अनुमानित फायदा चाहती है। अपनी इस प्रकार के गठबंधन में गठबंधन के सहयोगी दलों का एक मात्र उद्देश्य होता है कि जितना वे इन्वेस्ट करते है उसका अधिकतम फायदा वे प्राप्त कर सके।

भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दल जैसे बसपा, सपा, डीएमके, एआईएडीएमके, टीडीपी, बीजेडी, जेएमएम आदि अनेक पार्टियां गठबंधन में केवल अपने हित के लिये ही जुड़ते है और जैसे ही इन्हें लगता है कि उनका हित इस गठबंधन के साथ नहीं हो पा रहा, वे गठबंधन से हटने में भी नहीं हिचकिचाते। राष्ट्रहित इनके ऐजेन्डा में नहीं होता। फरवरी-मार्च २००५ के चुनाव में बिहार में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ सभी दलों द्वारा अपने फायदे के हिसाब से गठबंधन करने का प्रयास किया किन्तु इन दलों को होने वाला राजनैतिक फायदा इन्हें हो रहे नुकसान की तुलना में अधिक प्रतीत हुआ इसी कारण रामविलास पासवान ने एक ओर जहां लालू प्रसाद यादव के साथ जाने से इंकार किया वहीं भारतीय जनता पार्टी से भी उन्होंने दूरी बनाये रखी और सारे प्रयास विफल होने के उपरांत वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा।

६.लायर एण्ड यंग फिलासाफी

लायर और यंग ने गठबंधन के लिए तीन तत्वों को महत्वपूर्ण माना-
१.विचारधारा समानता
२.सफलता की गुंजाईश
३.फायदा या नुकसान

ठनका मानना है कि विभिन्न दल जब भी गठबंधन की ओर अग्रसर होते है तब वे गठबंधन से उन्हें होने वाला फायदा गठबंधन में सफलता की गुंजाईश और अपने से समान विचारधारा इन तत्वों को प्राथमिकता देते हैं इनमें भी अधिकतम फायदे की बात नजर आती है वहीं गठबंधन निर्माण का आधार बनाता है।

आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक गठबंधन में तीनों ही स्थितियां लागू हो किन्तु इसमें से अधिकतम स्थितियां जब लागू होती है तब ही सही गठबंधन बन पाता है।

इन तीनों तत्वों में गठबंधन निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिन्दु किसी एक दल विशेष को होने वाला फायदा है। प्रत्येक दल यह चाहता है कि उसे और उसके सदस्यों को अधिकाधिक राजनैतिक व आर्थिक फायदा हो अगर उसे कहीं नुकसान होते दिखता है तो वह गठबंधन से तत्काल स्वयं को पृथक कर लेता है। जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन और फिर उनका अलग होना तथा भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी द्वारा छः-छः महीने के मुख्यमंत्री का प्रयोग और उसकी असफलता आदि। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु विचारधारात्मक समानता होता है। समान विचारधारा वाले दलों के बीच गठबंधन तुलनात्मक रूप से अधिक समय तक चलता है और इनके बीच मतभेद हो जाने की स्थिति में उन्हें दूर करने के रास्ते भी तुलनात्मक रूप से आसानी से निकल जाते है। जैसे प. बंगाल में पिछले ३० वर्षों से साम्यवादी गठबंधन सरकार अस्तित्व में है। चूंकि गठबंधन में शामिल सभी दल समानवादी विचारधारा के है, अतः इनके बीच के मतभेद गहराने के पहले ही सुलझा लिये जाते हैं और अंतिम तत्व जिसे की गठबंधन निर्माण में प्रमुखता दी जाती है वह है सरकार की स्थिरता भारतीय राजनीति की यह बड़ी कमी ही है कि जिस तत्व को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिये था उसी की सर्वाधिक अवहेलना की जाती है।

उपर के दो डवकमस ैवबपंस च्ेलबीवसवहल डवकमस ंदक ैपकमे स्वहतमंसकपेजंदबम डवकमस दो उपकल्पनाओं पर आधारित है।

हर पार्टियों के विश्वासी निर्णय जुड़ने की इच्छा में विचारधारा ही महत्वपूर्ण तत्व होता है।

७.पाल ब्रास विचारधारा

जातिगत विभिन्नता और विभेद के आधार पर गठबंधन राजनीति के अध्ययन का प्रयास पाल ब्रास द्वारा किया गया। पाल ब्रास ने थ्बजपवदंसप्रउ पर अपना अध्ययन उत्तर भारतीय राज्यों पर किया और वे परिणाम तक पहुंचे कि यहां पर जाति के भीतर के मतभेदों की तुलना में इसे दो या अधिक जातियों के बीच कके मतभेद ज्यादा है और ये ही गठबंधन की राजनीति का आधार तैयार करते है।

हार्डिमान ने प. बंगाल के अपने अध्ययन के दौरान पाल ब्रास की विचारधारा का खण्डन किया और उसने इस प्रकार के जाति के आधार पर विभिन्न विभेद नहीं पाये।

फ्रेन्डा ने प. बंगाल सरकार (गठबंधन) के अध्ययन के दौरान कहा कि विभिन्न क्षेत्रीय दलों को धर्म, जाति, वर्ग, सम्प्रदाय के आधार पर सामंजस्य बिठाकर ही गठबंधन का प्रयास किया जाना चाहिये। उनके सामंजस्य से ही राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण हो सकता है। कांग्रेस और सीपीआई में होने वाली टूट-फूट को उन्होंन उपक्षेत्रीय धारणा के रूप में परिभाषित किया।

इन सभी अध्ययनों की एक विशेष कमी यह रही कि इन्होंने केवल समय विशेष के चुनाव परिणामों और स्थितियों को ही आधार बनाया। इन्होंने कभी भी भारतीय राजनैतिक व्यवस्था में गठबंधन की समृद्ध परम्परा की ओर ध्यान नहीं दिया। आजादी के दौरान स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न दलों की एकजुटता आजादी के बाद के विभिन्न आंदोलन संविधान निर्मात्री समिति, सभी जगह तो गठबंधन थे किन्तु इनके द्वारा किसी का भी ध्यान नहीं गया।

अधिकांश पश्चिम के ैबीवसमतश् ने बंगाल के भद्रलोक फार्मूले को मान्यता दी। कुछ हद तक ये लाग अभिजनवादी सिद्धांत से प्रेरित हुए है। बंगाल की राजनीति में राजा राममोहन राय, विद्यासागर जी, विवेकानंदजी आदि अनेक महान व्यक्तियों ने अपने विचार प्रस्तुत किये जिनका अनुसरण आम जनता के द्वारा किया गया।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

१. निर्वाचन आयोग रिपोर्ट (वेबसाईट) लोकसभा चुनाव वर्ष १९८९, १९९६, १९९७।
२. इंडिया टुडे, नई दिल्ली, १० मई १९९९, पृ.४-८।
3. Mazid Akhtar- Coalition Politics and Power Sharing, p.179.
4. Mazid Akhtar- Coalition Politics and Power Sharing, p.187.
5. दैनिक नईदुनिया, इन्दौर, दिनांक २१ मई १९६८, पृ.१।
6- नागपाल, ओम, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, शासन और राजनीति, कमल प्रकाशन, इन्दौर, पृ.१४९।
7- दैनिक नईदुनिया इन्दौर, दिनांक १८ फरवरी, १९६८, पृ.१।
8. Coalition Politics and Power Sharing, p.84.

9. Samuel S. Bacharach and Edward J. Lawler Power and Plitics in Organization- The Social Psychology of Conflict Coalition and Barganing, p.3, California, 1980.
10. Michael Lieserson, Game Theory and the Study of Coalition Behavior, in Groennings (Ed) p.256.
11. B. Bhattacharya, The U.F. and the left in Bengal, in Coalition Government in India, Op. Cit. p.290.
13. Tagore Soumendra Nath, The People's Front or Front Against the people, see against the stream, Vol. 2, p.10, Calcutta, 1984.
14. Seven Groennings et al (ed.) The Study of Coalition Behavior p.7, Halt Rinehart and Winston Inc, 1970.
15. Micheal Lieserson, Game Theory and the study of Coalition Behavior, In Groennings (ed.) p.264.
16. David Hardiman, The Indian Faction in Subaltern Studies, Vol. I, p.203-13.
17. Marcus Franda Political Development and Political Decay in Bengal, p.7, Orient Longman, 1970.

१८. नागपाल ओम- भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, शासन और राजनीति, कमल प्रकाशन, इन्दौर, पृ.१५१।
१९. डॉ. सत्या एम. राय- भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद- हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पृ.५७९।
२०. फडिया, बी.एल. एवं जैन पुखराज- भारतीय शासन और राजनीति, साहित्य भवन, आगरा, पृ.४५९।
२१. भारतीय राजव्यवस्था, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, पृ.डी-५ से डी-१०।
२२. N.C. Sahni, Coalition Politics in India (New Academic Publishing Company, Jalandhar, 1971) p.29.
२३. काश्यप सुभाष, हमारा संविधान, भारत का संविधान और संवैधानिक विधि, नेशनल बुक ट्रस्ट इंण्डिया, नई दिल्ली, पृ.३३।
२४. डॉ. सत्या एम. राय- भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद- हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पृ.१५६-१६१।